अनुलग्नक-III

अन्य औद्योगिक गलियारा परियोजनाएं

चेन्नई बेंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर (CBIC)

चेन्नई बेंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रत्येक सीबीआईसी राज्य की आंतरिक मूलभूत क्षमताओं और योग्यताओं से लाभ उठाते हुए समग्र दृष्टिकोण से अवसंरचना संकुलन से निबटने पर विचार करता है। तदनुसार, पारदर्शी और निवेश हितैषी सुविधा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कोरिडोर के भीतर, महत्वपूर्ण स्थानों पर अत्यधिक प्रभावी/बाजार प्रेरित नोड्स विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार, इन क्षेत्रों में विश्व श्रेणी अवसंरचना, पत्तनों तथा लॉजिस्टिक्स हबों माल यातायात के आवागमन हेतु सड़क एवं रेल संपर्कत्ता, विश्वसनीय उर्जा द्वारा सेवित, गुणवत्तावान सामाजिक अवसंरचना और व्यापार स्थापित करने के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धी सहयोगी वातावरण कराने के लिए इन नोड्स को आत्मनिर्भर बनाने का प्रस्ताव है।

सीबीआईसीक्षेत्र में तीन राज्य(यथा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश) शामिल है, जिन्हें सीबीआईसीराज्य कहा जाता है। सीबीआईसी क्षेत्र में लगभग 47.5 मिलियन जनसंख्या रहती है जो देश की कुल जनसंख्या का 3.7 प्रतिशत है।

वर्तमान स्थिति:

- आंध्र प्रदेश में **कृष्णपट्नम नोड** के लिए, शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट निष्पादित किया गया है और एनआईसीडीआईटी कृष्णपट्नम इंडस्ट्रियल सिटी नामक संयुक्त उपक्रम निगमित किया गया है। कार्यशील क्षेत्र (2500 एकड़) में विस्तृत मास्टर योजना और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। एनआईसीडीआईटी ने दिनांक 30 अगस्त 2019 को आयोजित अपनी बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया और इसे सीसीईए के अंतिम अनुमोदन के लिए भेजने की सिफारिश की है।

- कर्नाटक में **तुमकुरुनोड** के लिए, शेयरहोल्डर्सएग्रीमेंट और स्टेट सपोर्टएग्रीमेंट को निष्पादित किया गया है और सीबीआईसीतुमकुरुइंडस्ट्रियलटाऊनशिप लिमिटेड नामक संयुक्त उपक्रम निगमित किया गया है।कार्यशील क्षेत्र (1736 एकड़) में विस्तृत मास्टर योजना और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियों को अंतिम रूप दे दिया गया है।एनआईसीडीआईटी ने दिनांक 30 अगस्त 2019 को आयोजित अपनी बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया और इसे सीसीईए के अंतिम अनुमोदन के लिए भेजने की सिफारिश की है।

- तमिलनाडु में पोन्नेरीनोड के लिए, राज्य सरकार ने शेयरहोल्डर्सएग्रीमेंट और स्टेट सपोर्टएग्रीमेंट के लिए अपनी सहमति दे दी है। एनआईसीडीआईटी ने दिनांक 30 अगस्त 2019 को आयोजित अपनी बैठक मेंएसपीवी गठन के लिए अनुमोदन सहित इसका अनुमोदन दे दिया है।

अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियलकोरिडोर (एकेआईसी)

भारत सरकार छः राज्यों में फैले 1839 किमी लंबे पूर्वी समर्पित यातायात गलियारे के संरेखण के साथ अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियलकोरिडोर विकसित कर रही है। एकेआईसी का उद्देश्य क्षेत्र की मौजूदा आर्थिक और रोजगार क्षमता का इष्टतमीकरण, विशेषकर निर्माण, एग्रो प्रोसेसिंग, सेवाओं और निर्यात उन्मुखी इकाइयों में निवेश बढ़ाना और उच्च मानक अवसंरचना और सक्षम व्यापिरक वातावरण का निर्माण कर क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। ईडीएफसी के दोनों ओर 150-200 किमी के

क्षेत्र में एकेआईसी को चरणबद्ध तरीके से विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। एकेआईसी का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में होगा।

वर्तमान स्थिति:

- संभावी योजना तैयार कर ली गई है।
- विकास के लिए सात (7) एकीकृत निर्माण क्लस्टर पहचाने गए है, यथा:

  - पंजाब- (राजपुरा-पटियाला),
  - उत्तराखंड (प्राग-खुरपियाफार्म्स),
  - उत्तर प्रदेश (भौपुर),
  - बिहार (गमहरिया),
  - झारखंड (बरही),
  - पश्चिम बंगाल (रघुनाथ पुर)
  - हरियाण (साहा)

- पश्चिम बंगाल में आईएमसी साइट के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य चालू है जहां 2483 एकड़ भूमि उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट को सहमति दे दी है।

विजाग-चेन्नई इंडस्ट्रियलकोरिडोर:

कोलकाता-चेन्नई-तूतीकोरिन को जोड़ते हुए पूर्व तट आर्थिक गलियारे के भाग के रूप में इस पर विचार किया गया था। वीसीआईसी क्षेत्र में उद्योगों, खनिज का सबसे बड़ा घनत्व है और इसके अंतःप्रदेश के अच्छे संपर्क और पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्था के नजदीक बड़े पत्तनों के साथ अच्छे स्थानीय कारक (आंध्र प्रदेश की लगभग 80 प्रतिशत) द्वारा पूरक किए जाते हैं।

वर्तमान स्थिति:

- एशियाई विकास बैंक द्वारा अवधारणात्मक विकास योजना पूरी कर ली गई है।
- एडीबी ने वीसीआईसी परियोजना के आंध्र प्रदेश सरकार को 500 मिलियन अमेरिकी डालर का प्रोजेक्ट ऋण और 125 मिलियन अमेरिकी डालर का प्रोग्राम ऋण अदनुमोदित किया है।
- प्राथमिकता वाले नोडविशाखापटनम और चित्तूर है।
- एनआईसीडीआईडीटी ने 30 अगस्त को अपनी बैठक में विशाखापटनम और चित्तूर को वीसीआईसी के प्रथम चरण के रूप में प्राथमिकता वाले नोड के रूप में विकास के लिए अनुमोदन दे दिया है।

बेंगलूररू मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (बीएमआईसी)

भारत सरकार बेंगलूरू और मुंबई के बीच भी बेंगलूरू मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर विकसित कर रही है

जिसका कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों पर व्यापक प्रभाव होगा।

बेंगलूरू मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर का उद्देश्य दो राज्यों को नवोन्मेष, निर्माण, रोजगार सृजन और संसाधन सुरक्षा के अनुसार महत्वपूर्ण लाभ लेते हुए विश्व श्रेणी स्थायी संपर्कत्ता अवसंरचना द्वारा एक सुनियोजित एवं संसाधन कुशल औद्योगिक आधार का विकास को सुगम बनाना है। कोरिडोर के साथ विश्व श्रेणी अवसंरचना की उपलब्धता दो राज्यों में निर्माण तथा औद्योगिक गतिविधियों में निवेश सक्षम बनाएगा। अधिक कंपनियों को आकर्षित करना, विशेषकर निर्माण कंपनियां स्थानीय निर्माणकर्ताओं की वैश्विक प्रतियोगितात्मकता मजबूत करने में प्रभावी होंगी जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय विकास होगा।.

<u>वर्तमान स्थिति:</u>

- भावी योजना तैयार कर ली गई है।
- आगे कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक नोड के रूप में कर्नाटक के धारवाड नोड को चुना गया है।
- महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सांगली/शोलापुर नोड के विकास के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है।